शत्रुघन इस्सर

बनाम

श्रीमती सुबुजपारी और अन्य

4 अगस्त, 1966

[के.एन वांचू, जे.सी. शाह व आर. एस. वछावत जे.जे.]

हिंदू महिला संपत्ति अधिकार अधिनियम 18/1937 धारा 3(2), 3(3)सहदायिकी संपत्ति में विभाजन का दावा करने वाली हिंन्दु विधवा का मामला - क्या सहदायिकी संपत्ति में अन्य सहदायिको का उत्तरजीविता का अधिकार समाप्त होता है- विधवा के हित की प्रकृति- उसका न्यागमन।

सी ,एक हिन्दू विधवा, ने अप्रैल 1949 में एक मुकदमा अपने मृतक पति के संपार्शविकों के विरूद्ध सहदायिकी में विभाजन हेतु किया। उस सहदायिकी में सदस्य उसका पति था। मामला यह है कि उसके पति 1934 में सहदायिकी से अलग हो गये थे अक्टूबर 1937 में उनकी मृत्यु पर संपत्ति में का उनका हिस्सा हस्तांरित कर दिया गया। लेकिन प्रतिवादी विफल रहे और संपत्ति विभाजित करने और उन्हें विरासत में मिले हिस्से को देने में लापरवाही की। सी की मृत्यु 1951 में हुई और उनकी दो बेटियों को प्रतिवादियों द्वारा उनके उत्तराधिकारी व विधिक प्रतिनिधियों के रूप में दर्ज किया गया।

विचारण न्यायालय ने वाद को इस आधार पर खारिज कर दिया कि 1934 में सी के पति को सहदायिकी से अलग करने का तर्क स्थापित नहीं किया गया था और सहदायिकी में उनकी संपत्ति अन्य सहदायिकों में न्यागमित कर दी गई थी। अपील में उच्च न्यायालय द्वारा विचारण न्यायालय के इस निर्णय को उलट दिया गया और संपत्ति में हिस्से के कब्जे के लिए डिक्री प्रदान की।

इस न्यायालय में अपील पर,

यह धारित किया गया कि उच्च न्यायालय द्वारा मामले में सही निर्णय सुनाया गया था हालांकि यह स्थापित नहीं हुआ था कि सी का पति 1934 में सहदायिकी से अलग हो गया था। 1937 में उसकी मृत्यु के बाद ,1937 के अधिनियम 18 की धारा 3 के क्रियान्वयन द्वारा सी के पति की संपत्ति को सी में निवेशित किया गया। जब उसने विभाजन के लिए वाद दायर किया तो वह हित परिभाषित हो गया और पति के सहदायिकों के सभी दावों से मुक्त होकर उसमें निहित हो गया। सी की मृत्यु पर भले ही हित की सीमा अलग नहीं थी और यह उसके विशेष अधिकार में नहीं था इसे पति के निकटतम उत्तराधिकारियों में न्यागमित कर दिया गया।

एक सहदायिकी में विधवा को 1937 के अधिनियम 18 की धारा 3(2) द्वारा उसी हित के साथ निवेशित किया जाता है जो हित उसके पति का सहदायिकी संपत्ति में था। विधवा का सहदायिकी में प्रवेश किया जाता है और उसके पति के जीवित सहदायिक व विधवा के स्वामित्व का हित उत्तपन्न होता है विधवा केवल इस कारण से कि उसने सहदायिकी में पति के स्थान पर प्रवेश किया है सहदायिक नहीं बन सकती, जैसा कि पति को अधिकार प्राप्त होता है जो वह अन्य सहदायिकों के ऊपर प्रयोग कर सकता था। अपने पति की सहदायिकी संपत्ति में विधवा के हित के प्रतिस्थापन के कारण अन्य सहदायिकों को मिताक्षरा विधि के अंतर्गत उत्तरजीविता के नियम के अनुसार हित निलंबित रहेगा, जब तक कि विधवा संपत्ति सुनिश्चित करती है, यद्यपि

प्राप्त हुआ हित धारा 3(2) के अंतर्गत विभाजन प्रतिबंधों के अधीन है जो संपत्ति में निहित है, विधवा के पास अभी भी यह शक्ति है कि वह पुरूषस्वामी की तरह विभाजन की मांग कर अपना हित सुनिश्चित करे। यदि विधवा को उस परिवार में शामिल किया जाता है जिसमें उसका पति था, वह अपनी संपत्ति की समाप्ति पर विभाजन की मांग नहीं करती, तो उसका हित सहदायिकी संपत्ति में विलीन हो जायेगा लेकिन यदि वह विभाजन का दावा करती है तो वह दूसरे सहदायिकों से अलग हो जाती है और उसका हित सहदायिकी संपत्ति में एक परिभाषित हित बन जाता है और अन्य सहदायिकों का अधिकार उत्तरजीविता द्वारा उस हित को लेने हेतु समाप्त हो जाता है। यदि विभाजन के बाद उसकी मृत्यु हो जाती है या उसकी संपत्ति अन्यथा निर्धारित की जाती है तो सहदायिकी संपत्ति में वह हित जो उसमें निहित है वह उसके पति के उत्तराधिकारियों में निहित हो जाएगी। यह मान लेना कि कुछ निर्णित मामलों में यह धारित किया गया कि सहदायिकों को अपना हित लेने का अधिकार विधवा के हित निर्धारण के बाद भी जीवित रहता है। वाद दायर करने के कारण विधवा का हित निश्चित हो गया और अन्य सहदायिक विभाजन का दावा करने से वंचित हो जाते हैं।

लक्ष्मी पेरूमल्लू बनाम कृष्णवेन्नमा,[1965] 1 S.C.R 26 संदर्भित किया मोया सुब्बाराव और अन्य बनाम मोयाकृष्णा प्रसादम और अन्य, I.L.R [1954] मद्रास 257; श्यामराव भगवन्तराम बनाम काशीबाई और अन्य, A.I.R 1956 नागपुर,110 एवं भगवत बनाम भाईवलाल एवं अन्य I.L.R [1957] M.P 114, अस्वीकृत । परप्पागरी परप्पा उर्फ हनुमंत थप्पा और अन्य बनाम परप्पागरी नागाम्मा और अन्य I.L.R[1954] मद्रास 183, स्वीकृत।

जब तक विधवा वाद द्वारा या अन्य निजी व्यवस्थाओं द्वारा सहदायिकी संपत्ति में के अपने हित को अनन्य कब्जे में नहीं लेती है तब तक सहदायिकों को विधवा में निहित हित लेने के लिए कहा जाता है। विधवा जिस अधिकार का दावा कर सकती है वह उस अधिकार से अलग नहीं है जिसका दावा उसका पति कर सकता था यदि वह जीवित होता। इसीलिए सहदायिक की मृत्यु पर उत्तरजीविता द्वारा संपत्ति लेने हेतु सहदायिकों द्वारा विधवा से विभाजन की मांग को नहीं माना जा सकता।

गिरियाबाई बनाम सदाशिव ढुढियारी और अन्य L.R 43 I.A 151 संदर्भित प्रतापमुल अग्रवाल बनाम धनवती बीबी और अन्य। L.R 63 I.A 33 प्रतिष्ठित।

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: 1963 की सिविल अपील संख्या 939। 1951 की मूल डिक्री संख्या 458 से अपील में पटना उच्च न्यायालय के 28 मार्च, 1958 के फैसले और डिक्री के खिलाफ अपील।

सरजू प्रसाद, इंदु शेखर प्रसाद सिन्हा, बीपी सिंह. अपीलार्थी की ओर से अनिल कुमार सबलोक एवं यूपी सिंह। एनसी चटर्जी और डी. गोबरधुन, या उत्तरदाता संख्या 1 और

2. प्रतिवादी संख्या 9 के लिए आरबी दातार, विनीत कुमार और केआर चौधरी।

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति शाह द्वारा सुनाया गया, बाबूजी की विधवा मुसामत चंदो कुएर ने 23 अप्रैल, 1949 को दरभंगा के अधीनस्थ न्यायाधीश की अदालत में अपने पति के संपार्शविकों के विरूद्ध विभाजन की डिक्री और अनुसूची ए से ई में वर्णित संपत्तियों में आधे हिस्से का अलग कब्ज़ा और अनुसूची में चौथा हिस्से हेतु एक वाद दायर किया। एफ वादपत्र के साथ संलग्न है। चंदो कुएर का मामला यह था कि उनके पति बाबूजी 1934 में उस सहदायिकी से

अलग हो गए, जिसके वे सदस्य थे, और 28 अक्टूबर, 1937 को उनकी मृत्यु पर पारिवारिक संपत्ति में उनका हिस्सा उन्हें न्यागत हो गया, लेकिन प्रतिवादी विफल रहे और संपत्ति का बंटवारा करने में और उसे विरासत में मिला हिस्सा देने में उपेक्षा की। बाबूजी के संपार्श्विकों द्वारा मुकदमे का विरोध किया गया। 9 मार्च, 1951 को चंदो कुएर की मृत्यु हो गई, और उनकी बेटियों सुबुजपारी और सुजन देवी (इसके बाद सामूहिक रूप से 'अपीलकर्ता' कहा जाता है) को उनके उत्तराधिकारी और कानूनी प्रतिनिधियों के रूप में मुकदमे के रिकॉर्ड में लाया गया।

इस राय के चलते कि 1934 में बाबूजी को सहदायिकी से अलग करने की याचिका स्थापित नहीं हुई थी, और सहदायिकी संपत्ति में बाबूजी का हित जीवित सहदायिकों को हस्तांतरित हो गया था, विचारण न्यायालय ने मुकदमे को खारिज कर दिया। अपील में, पटना उच्च न्यायालय ने मुकदमे की तारीख पर संपत्ति में एक हिस्से के कब्जे की डिक्री दे दी। यह माना गया कि 28 अक्टूबर, 1937 को बाबूजी की मृत्यु पर, चंदो कुएर ने हिंदू महिला संपत्ति अधिकार अधिनियम , 1937 के आधार पर, सहदायिक संपत्ति में वही हित अर्जित किया जो बाबूजी का था, और संस्था द्वारा विभाजन के मुकदमे में हित परिभाषित हो गया और उसकी मृत्यु के बाद यह अपीलकर्ताओं को बाबूजी की संपत्ति के उत्तराधिकारी के रूप में न्यागत हो गया। उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए प्रमाण पत्र के साथ घिरन के पुत्र शत्रुघन ने इस न्यायालय में अपील की है।

हिंदू विधि के मिताक्षरा शाखा के अंतर्गत, एक सहदायिक की मृत्यु पर सहदायिकी संपत्ति में उसका व्यक्तिगत हित शेष सहदायिकों को उत्तरजीविता द्वारा हस्तांतरित हो जाता है, और उसकी विधवा यदि कोई हो तो केवल संपत्ति से भरण-पोषण की हकदार होती है। लेकिन संसद ने 1937 के अधिनियम 18 द्वारा अधिनियमित किया, जिसमें विधवा को मिताक्षरा विधि द्वारा शासित परिवार में उसी हित के साथ निवेशित करने की मांग की गई, जो उसके पति की मृत्यु के समय पारिवारिक संपत्ति में था, और विभाजन द्वारा प्राप्त करने का अधिकार भी था। अलग हित 1938 के अधिनियम 11 द्वारा संशोधित 1937 के अधिनियम 18 की धारा 3,(जहां तक यह इस अपील में महत्वपूर्ण है)

> "3. (1)
>
> (2) जब दयाभाग शाखा या प्रथागत विधि के अलावा हिंदू विधि के किसी भी शाखा द्वारा शासित एक हिंदू की मृत्यु हो जाती है, उसका मृत्यु के समय हिंदू संयुक्त परिवार की संपत्ति में हित होता है, तो उसकी विधवा का भी वही हित होगा जो स्वयं उसका था यह उपधारा (3) के प्रावधानों के अधीन होगी।
>
> (3) इस धारा के प्रावधानों के अंतर्गत हिंदू विधवा को दिया जाने वाला कोई भी हित सीमित होगा। हित को एक हिंदू महिला की संपत्ति के रूप में जाना जाता है, बशर्ते कि उसे पुरुष स्वामी के रूप में विभाजन का दावा करने का समान अधिकार होगा।

यह अधिनियम प्रांतों में कृषि भूमि के उत्तराधिकार को विनियमित करने के लिए प्रावधान नहीं करता है, लेकिन बिहार प्रांत ने 1942 के अधिनियम VI को अधिनियमित किया, जिसमें 1937

के अधिनियम 18 के संचालन को 14 अप्रैल, 1937 से पूर्वव्यापी प्रभाव से बिहार में कृषि भूमि तक बढ़ा दिया गया।

यह अधिनियम सहदायिकी संपत्ति की अवधारणा और परिवार के सदस्यों के सहदायिक संपत्ति के अधिकारों में मूलभूत परिवर्तन करने का प्रयास करता है। प्राचीन कानून निर्माताओं द्वारा प्रतिपादित कुछ बुनियादी अवधारणाओं के आलोक में एंग्लो-इंडियन न्यायालयों द्वारा परिश्रमपूर्वक विकसित किए गए हिंदू कानून ने स्थिरता और समरूपता हासिल कर ली थी। सहदायिक सदस्य की विधवा को उस हित के साथ निवेशित करने का अधिनियम जो उस सदस्य के पास उसकी मृत्यु के समय था, ने ऐसे परिवर्तन पेश किए है जो सहदायिकी की संरचना से अलग हैं। विधवा का हित विरासत या उत्तरजीविता से नहीं, बल्कि वैधानिक प्रतिस्थापन से उत्पन्न होता है। लक्ष्मी पेरूमल्लू बनाम कृष्णवेनम्मा। संपत्ति में उसका हित एक सीमित हित है जिसे एक हिंदू महिला की संपत्ति के रूप में जाना जाता है: लेकिन अधिनियम उसे विभाजन का दावा करने की वही शक्ति देता है जो एक पुरुष स्वामी के पास है।हालांकि, अधिनियम विभाजन पर प्राप्त संपत्ति के हस्तांतरण के तरीके के बारे में, उसकी संपत्ति की समाप्ति पर, विधवा में निहित हित के लिए जीवित सहदायिकों के अधिकारों के बारे में, जीवित के हित के लिए विधवा के अधिकारों के बारे में चुप है। सहदायिक, और कई अन्य मामलों के बारे में हमारे सामने उठाई गई समस्या को हल करने के लिए, हम पहले उदाहरण में एक हिंदू सहदायिकी की प्रमुख विशेषताओं और हिंदू महिलाओं द्वारा रखी गई सीमित संपत्ति का उल्लेख कर सकते हैं जिसे हिंदू महिला की संपत्ति के रूप में जाना जाता है।

मिताक्षरा विधि के अंतर्गत एक हिंदू सहदायिकी में केवल पुरुष शामिल होते हैं: इसमें केवल वे सदस्य शामिल होते हैं जो सहदायिकी संपत्ति में जन्म या गोद लेने के आधार पर हित प्राप्त करते हैं। सहदायिकी संपत्ति का सार स्वामित्व की एकता से है जो सहदायिकों के पूरे समूह में निहित होता है। हालाँकि यह संयुक्त रहता है, कोई भी व्यक्तिगत सदस्य अविभाजित संपत्ति का यह अनुमान नहीं लगा सकता है कि उसमें उसका एक निश्चित हिस्सा है। प्रत्येक सहदायिक का हित उतार-चढ़ाव वाला होता है, जो मृत्यु से बढ़ सकता है, और सहदायिकों के पुत्रों के जन्म से कम हो सकता है: केवल विभाजन पर ही सहदायिक यह दावा कर सकता है कि वह एक निश्चित हिस्से का हकदार बन गया है। सहदायिक संपत्ति की दो प्रमुख घटनाएं हैं: सहदायिकों का हित उत्तरजीविता से हस्तांतरित होता है, न कि विरासत से; और यह कि सहदायिक का पुरुष जन्म से सहदायिक संपत्ति में हित प्राप्त करता है, अपने पिता का प्रतिनिधित्व करने के रूप में नहीं बल्कि जन्म से प्राप्त अपने स्वतंत्र अधिकार के रूप में।

एक हिंदू महिला द्वारा विरासत में मिली संपत्ति, जो विवाह द्वारा मृत स्वामी के गोत्र में प्रवेश कर चुकी है, हिंदू विधि के सभी शाखाओं के अनुसार एक विधवा या एक हिंदू महिला जो संपत्ति प्राप्त करती है। उस संपत्ति में उसका अधिकार एक मालिक का है, न कि आजीवन किरायेदार का , जो संपत्ति उसमें निहित है और वह उस संपत्ति का पूरा प्रतिनिधित्व करती है: जब तक वह जीवित है, उसके द्वारा रखी गई संपत्ति में किसी का कोई निहित हित नहीं है। हालाँकि, उसके अलगाव के अधिकार प्रतिबंधित हैं: वह संपत्ति के कोष को केवल कानूनी आवश्यकता या संपत्ति के लाभ के लिए अलग कर सकती है। एक हिंदू महिला की सीमित संपत्ति उसके द्वारा रखी गई

संपत्ति में स्वामित्व को दर्शाती है, जो कि अंतिम पूर्ण स्वामी के उत्तराधिकारियों को महिला की संपत्ति के विलुप्त होने पर उस संपत्ति के अलगाव और न्यागमन की शक्ति पर प्रतिबंध के अधीन है।

अधिनियम द्वारा कुछ विरोधाभासी अवधारणाओं में सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास किया गया है। एक सहदायिक की विधवा को अधिनियम द्वारा उसी हित के साथ निवेशित किया जाता है जो उसके पति की मृत्यु के समय सहदायिकी संपत्ति में था। इस प्रकार उसे सहदायिकी में शामिल किया जाता है, और उसके पति के जीवित सहदायिकों और इस प्रकार प्रस्तुत की गई विधवा के बीच हितों का समुदाय और स्वामित्व की एकता उत्पन्न होती है। लेकिन उस कारण से विधवा सहदायिक नहीं बन जाती है यद्यपि संपत्ति में उसके पति के समान हित के साथ निवेश करने पर भी वह अधिकार प्राप्त नहीं कर पाती है जिसका प्रयोग उसका पति अन्य सहदायिकों के हितों पर कर सकता था। अपने पति के स्थान पर सहदायिकी संपत्ति में उसके हित के वैधानिक प्रतिस्थापन के कारण, हिंदू विधि की मिताक्षरा शाखा के अंतर्गत अन्य सहदायिकों को उत्तरजीविता के नियम के अंतर्गत उस हित को लेने का अधिकार तब तक निलंबित रहता है, जब तक वह संपत्ति कायम रहती है। लेकिन सहदायिक की मृत्यु पर सहदायिकी संपत्ति में विधवा के पक्ष में एक परिभाषित हित निर्धारित करने के लिए सहदायिकी का कोई विघटन नहीं होता है। लक्ष्मी पेरुमल्लू बनाम कृष्णवेनम्मा। धारा 3(2) के अंतर्गत उसके द्वारा अर्जित हित विभाजन के अधीन है जो उसकी संपत्ति में निहित हैं। उसके पास अभी भी बंटवारे की मांग करने एवं अपने हित को सुनिश्चित करने की शक्ति है, जैसा कि एक पुरुष स्वामी कर सकता है। यदि विधवा अपने पति के परिवार में शामिल होने के बाद विभाजन की मांग नहीं करती है, तो उसकी संपत्ति की समाप्ति पर उसका हित सहदायिकी संपत्ति में विलीन हो जाएगा। लेकिन यदि वह विभाजन का दावा करती है, तो उसे अन्य सदस्यों से अलग कर दिया जाता है और उसका हित सहदायिकी संपत्ति में एक परिभाषित हित बन जाता है, और जीवित रहने पर अन्य सहदायिकों का उस हित को लेने का अधिकार समाप्त हो जाएगा। यदि वह विभाजन के बाद उसकी मृत्यु हो जाती है या उसकी संपत्ति अन्यथा निर्धारित की जाती है, तो सहदायिकी संपत्ति में जो हित उसमें निहित है, वह उसके पति के उत्तराधिकारियों को हस्तांतरित हो जाएगा। यह सत्य है कि एक विधवा को सहदायिकी संपत्ति में हित प्राप्त होता है धारा 3(2) के अनुसार वह हित उसे विरासत में नहीं मिलता है, लेकिन संपत्ति में का उसका अविभाजित हित समाप्त हो जाता है। हिंदू विधवा की संपत्ति समाप्त होने पर यह उसके पति के उत्तराधिकारियों को हस्तांतरित हो जाएगी। यह मान लेना कि जैसा कि कुछ निर्णयित मामलों में धारित किया गया है कि विधवा के हित के निर्धारण पर उसका हित लेने का सहदायिक का अधिकार, विभाजन के दावे के कारण, हित निश्चित हो जाने के बाद भी बना रहता है सभी वास्तविकताओं के विभाजन का दावा करने के अधिकार को नकारना है।

अपीलकर्ता के वकील ने तर्क दिया कि विधवा ने निहित हित का अधिकार जीवित सहदायिकों में तब तक निहित है जब तक कि विधवा, वाद या निजी व्यवस्था द्वारा सहदायिक की संपत्ति में अपने अनन्य हित को कम नहीं करती। उन्होंने प्रस्तुत किया कि धारा 3(3) में अभिव्यक्ति "विभाजन" का अर्थ केवल स्थिति का विच्छेद नहीं है, बल्कि विधवा द्वारा अनन्य अधिकार

ग्रहण के बाद हितों और सीमाओं के आधार पर हितों का विभाजन है। इस प्रस्तुतिकरण के लिए कोई वारंट नहीं है। विधवा को विधि द्वारा विभाजन का दावा करने का वही अधिकार प्राप्त है जो एक पुरुष स्वामी के पास है और जैसा कि गिरिया बाई बनाम सदाशिव धुंडीराज और अन्य में प्रिवी काउंसिल की न्यायिक समिति द्वारा बताया गया है।

> "हिंदू कानून में, "विभाजन" का अर्थ संपत्ति को विशिष्ट शेयरों में विभाजित करना नहीं है; इसमें शीर्षक का विभाजन और संपत्ति का विभाजन दोनों शामिल हैं। मिताक्षरा में, विज्ञानेश्वर ने "विभाग" शब्द को परिभाषित किया है ", जिसे आम तौर पर अंग्रेजी में "विभाजन" शब्द द्वारा अनुवादित किया जाता है, "कुल के विशेष भागों में उन्हें वितरित करके संपूर्ण के संबंध में विविध अधिकारों का समायोजन।" मित्र मिश्रा ने विरोमित्रोदय में इस मार्ग का अर्थ समझाया है: वह दर्शाता है कि विज्ञानेश्वर की परिभाषा का अर्थ केवल संपत्ति का अधिकार देने के रूप में विशिष्ट शेयरों में संपत्ति का विभाजन नहीं है, बल्कि इसमें उन व्यक्तियों के संबंधित अधिकारों का पता लगाना शामिल है, जो संयुक्त रूप से विरासत का दावा करते हैं। वह कहते हैं (सरकार का अनुवाद, अध्याय ।,धारा 36); "विभाजन उस चीज़ से किया जाता है जिसमें मालिकाना अधिकार पहले ही उत्पन्न हो चुका है, परिणामस्वरूप विभाजन को संपत्ति को मालिकाना अधिकार के साधन के रूप में निर्धारित नहीं किया जा सकता है। वास्तव में, विभाजन से जो प्रभावित होता है वह केवल विशिष्ट शेयरों में मालिकाना अधिकार का समायोजन है"।

विभाजन का दावा करने का यह अधिकार, जिसका उपयोग एक पुरुष मालिक कर सकता है, एक हिंदू विधवा को धारा 3(3) द्वारा प्रदान किया गया है। बँटवारे के लिए दावा करने पर विधवा का हित परिभाषित हो जाता है। विधवा जिस अधिकार का दावा कर सकती है वह उस अधिकार से अलग नहीं है जिसका दावा उसका पति कर सकता था यदि वह जीवित होता, इसलिए सहदायिक की मृत्यु पर जीवित रहकर संयुक्त संपत्ति लेने का सहदायिक का अधिकार विभाजन की मांग के अनुरूप नहीं रह जाता है। सहदायिक में विधवा विधवा जो हित रखती है

वह हित विधवा को धारा 3(3) 1937 के अधिनियम 18 द्वारा प्राप्त होता है। उस हित से कोई सादृश्य नहीं है जो एक हिंदू संयुक्त परिवार की महिला सदस्य को अपने बेटों या पोते के बीच विभाजन पर आवंटित संयुक्त परिवार की संपत्ति में प्राप्त होता है। यह सच है, जैसा कि प्रतापमुल्ल अग्रवाल बनाम धनाबती बीबी और अन्य में धारित किया गया है कि मिताक्षरा विधि के अंतर्गत जब हिंदू संयुक्त परिवार में पारिवारिक संपत्ति का बंटवारा होता है तो पत्नी एवं मां के हिस्से शामिल होते हैं, जो कि उसकी हकदार होती हैं। लेकिन उन्हें मालिक के रूप में मान्यता नहीं दी जाती है। जब तक संपत्ति का विभाजन वास्तव में नहीं हो जाता, तब तक इस तरह के हिस्से का अधिकार नहीं है, क्योंकि भरण-पोषण के अधिकार के अलावा संपत्ति में उसके पास पहले से कोई अधिकार नहीं है। यदि संपत्ति के बंटवारे से पहले उसकी मृत्यु हो जाती है, तो संपत्ति में उसका हिस्सा वापस उस संपत्ति में आ जाता है जिससे वह अलग हुई थी। लेकिन जब एक हिंदू विधवा की संपत्ति का धारा 3(2) के अंतर्गत अधिग्रहण होता है तो संपत्ति के विभाजन से पहले भी उसका संपत्ति में एक हित होता है और वह हित तब परिभाषित हो जाता है जब उसके द्वारा विभाजन की स्पष्ट मांग की जाती है।

मोव्वा सुब्बा राव और अन्य बनाम मोव्वा कृष्ण प्रसादम और अन्य मामले में मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा धारित किया गया कि एक विधवा का हित एक व्यक्तिगत हित है जो उसकी मृत्यु पर समाप्त हो जाता है, इसे विधितः सही कथन नहीं माना जा सकता है।राव भगवंतराव बनाम काशीबाई और अन्य में नागपुर उच्च न्यायालय द्वारा विचार व्यक्त किया गया कि "एक विधवा को संयुक्त परिवार की संपत्ति में अपना हिस्सा प्राप्त करने का अधिकार है (विधवा द्वारा विभाजन के लिए दावा दायर करने के बाद भी)" हिंदू महिलाओं के लिए संपत्ति का अधिकार अधिनियम एक विशेष अधिनियम है। यह विधवा के साथ समाप्त हो जाता है, जब उसकी मृत्यु एक मुकदमे (उसके द्वारा दायर) की लंबित रहने के दौरान होती है। कार्रवाई का कारण उसके कानूनी प्रतिनिधियों तक नहीं बढ़ाया जाता है" और भागाबाई बनाम भैयालाल अन्य में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा विचार व्यकत किया गया कि "विभाजन के वाद के बाद मृत सहदायिक की विधवा द्वारा उसके मृत पति की संपत्ति अलग संपत्ति नहीं बन जाती है एवं विधवा की मृत्यु के बाद वह संपत्ति सहदायिकी में वापस चली जायेगी ", एक ऐसी धारणा पर आगे बढ़ें जो मिताक्षरा शाखा के अनुसार हिंदू विधि के अच्छी तरह से स्थापित नियमों के साथ असंगत है। यह धारणा कि यद्यपि अधिनियम द्वारा विधवा में निहित अधिकार संपत्ति का अधिकार है जो विभाजन की मांग पर सहदायिक संपत्ति से अलग हो सकता है, यह अभी भी विधवा की संपत्ति के निर्धारण पर सहदायिकी संपत्ति में वापस आने के लिए उत्तरदायी है, ऐसा नहीं है विधवा को "पुरुष स्वामी के रूप में विभाजन का दावा करने का समान अधिकार" प्रदान करने के वैधानिक अधिकार को पूर्ण रूप से प्रभाव नहीं देता।

परप्पागारी परप्पा उर्फ हनुमनथप्पा और अन्य बनाम परप्परागारी नागम्मा और अन्य के वाद में पूर्ण पीठ का फैसला सुनाते समय न्यायमूर्ति सुब्बा राव द्वारा निम्नलिखित टिप्पणियाँ की गईं। हमारे निर्णय में, समीक्षाधीन प्रश्न पर अधिनियम के प्रभाव को सही ढंग से निर्धारित करते हैं:

> "वह अपने पति के हिस्से का बंटवारा और अलग कब्ज़ा मांग सकती है। यदि वह बंटवारा मांगती है, तो बंटवारे की तारीख पर परिवार में उत्पन्न परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए उसके पति के हित पर तय किया जाना चाहिए। यदि उसने खुद को दूसरे से अलग कर लिया है उसके जीवनकाल के दौरान परिवार के सदस्यों में से, उसकी मृत्यु पर उत्तराधिकार उसके पति को इस आधार पर पता लगाया जाएगा कि संपत्ति उसकी अलग संपत्ति थी। यदि विच्छेद नहीं हुआ है, तो यह संयुक्त हिंदू परिवार के अन्य सदस्यों के जीवित रहने पर न्यागत हो जाएगा।"

विचारण न्यायालय द्वारा अभिलिखित किए गए निष्कर्ष पर, जिसे उच्च न्यायालय के समक्ष अपील में चुनौती नहीं दी गई, बाबूजी 1934 में अन्य सहदायिकों से अलग नहीं हुए। लेकिन अक्टूबर 1937 में उनकी मृत्यु हो गई और 1942 के बिहार अधिनियम 6 द्वारा संशोधित 1937 के अधिनियम 18 के संचालन से चंदो कुएर को उनके पति की सहदायिकी संपत्ति कृषि के साथ-साथ गैर-कृषि में भी निवेशित किया गया। जब उसने विभाजन के लिए मुकदमा दायर किया तो वह हित परिभाषित हो गया और उसे अपने पति के सहदायिकों के सभी दावों या अधिकारों से मुक्त कर दिया गया। चंदो कुएर की मृत्यु पर उत्तरजीविता द्वारा उस हित को लेने का सहदायिकों का अधिकार तब समाप्त हो गया था। उनकी मृत्यु पर, भले ही हित को सीमाओं से अलग नहीं किया गया था, और यह उनके अनन्य अधिकार में नहीं था, फिर भी यह उनके पति के

निकटतम उत्तराधिकारियों अर्थात उनकी बेटियों को हस्तांतरित हो गया। इसलिए उच्च न्यायालय द्वारा मुकदमे का उचित फैसला सुनाया गया।

अपील विफल होती है और जुर्माने के साथ खारिज की जाती है।

(डॉ० मंजरी रावल)
सिविल जज (जू०डि०)एफ०टी०सी०-1/
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
गाजियाबाद।